

08 November 2024

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना

सन्दर्भ: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में अध्ययन करने वाले छात्रों को बिना संपाश्विक (Collateral Free) और गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

- वित्तीय परिव्यय:** इस योजना के लिए 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए 3,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- लाभार्थी:** इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ब्याज सहायता से लगभग 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की संभावना है।
- ऋण गारंटी:** केंद्र सरकार 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी।
- ब्याज अनुदान:** जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और जो अन्य सरकारी छात्रवृत्तियों या ब्याज अनुदान योजनाओं के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें 3% ब्याज अनुदान मिलेगा। यह ब्याज अनुदान स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर लागू होगा।
- वार्षिक सहायता:** प्रत्येक वर्ष 1 लाख छात्रों को ब्याज अनुदान सहायता दी जाएगी।
- वरीयता मानदंड:** सरकारी संस्थानों के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

संस्थाओं की पात्रता:

- इस योजना में समग्र और डोमेन-विशिष्ट दोनों श्रेणियों में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले संस्थान शामिल होंगे।
- यह 101-200 रैंक वाले राज्य संचालित संस्थानों और सभी केंद्र सरकार संचालित संस्थानों पर भी लागू होगा।
- कुल 860 उच्च शिक्षा संस्थान इसके लिए पात्र होंगे, जिनकी सूची एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर प्रतिवर्ष अद्यतन की जाएगी।
- सभी पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता:** पिछली योजनाओं के विपरीत, यह योजना केवल तकनीकी या व्यावसायिक ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए उपलब्ध होगी।

वर्तमान योजनाओं की स्थिति में:

- यह योजना केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) के अतिरिक्त है, जो तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले उन छात्रों को लाभान्वित करती है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये तक है। इस योजना के तहत, ऐसे छात्रों को 10 लाख रुपये

तक के ऋण पर पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।



PM-Vidyalaxmi

Collateral-free, Guarantor-free Education Loans

Maximising access to quality Higher Education
for **Yuva Shakti**



Total outlay ₹ 3600 Crore



Financial assistance to meritorious students securing admission in top 860 HEIs of India



Benefitting 22 Lakh+ new students every year

विद्यालक्ष्मी योजना के सकारात्मक पहलू:

- बढ़ी हुई पहुंच:** गारंटर-मुक्त ऋण आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाते हैं, जिससे शिक्षा वित्तपोषण में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।
- योग्यता आधारित शिक्षा को प्रोत्साहन:** गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेने वाले छात्रों को ऋण प्रदान करके, यह योजना योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है, तथा प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- वित्तीय बोझ में कमी:** संपाश्विक और गारंटी आवश्यकताओं की अनुपस्थिति से छात्रों और उनके परिवारों पर वित्तीय तनाव कम हो जाता है, जिससे शिक्षा का खर्च उठाना आसान हो जाता है।
- नामांकन को बढ़ावा:** इस योजना से वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन दर में वृद्धि होने की उम्मीद है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के लिए।

आईटी अधिनियम के तहत विकिपीडिया की मध्यस्थ स्थिति को चुनौती

सन्दर्भ: हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विकिपीडिया को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत इसे मध्यस्थ के रूप में वर्गीकृत करने पर प्रश्न उठाए गए हैं। यह प्रश्न विकिपीडिया पर कथित पूर्वाग्रह और गलत जानकारी के प्रसार को

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR: 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR: 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029



ध्येयias.com

08 November 2024

लेकर उठे हैं।

- यह घटना सरकार की चिंता को दर्शाती है कि भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विनियमन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिनमें मध्यस्थ की भूमिका और उनके उत्तरदायित्व से संबंधित प्रभाव के मुद्दे होते हैं।

मध्यस्थ वर्गीकरण और उत्तरदायित्व की सुरक्षा:

- आईटी अधिनियम के तहत, मध्यस्थ वे प्लेटफॉर्म होते हैं जो बिना सामग्री को सीधे बनाए या नियंत्रित किए, तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई जानकारी को संग्रहित, प्राप्त या प्रसारित करते हैं। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन जैसे उदाहरण आते हैं।
- मध्यस्थों को कुछ कानूनी सुरक्षा प्राप्त है लेकिन यह स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना पड़ता है:
 - » **तटस्थ मंच की भूमिका:** मध्यस्थों को अपने प्लेटफॉर्म की सामग्री पर संपादकीय नियंत्रण नहीं रखना चाहिए।
 - » **समुचित परिश्रम का दायित्व:** मध्यस्थों को अवैध सामग्री को रोकने और आईटी नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामग्री वैध और अपमानजनक न हो।
- अगर मध्यस्थ इन शर्तों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें प्रकाशक के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है, जिससे उनका कानूनी उत्तरदायित्व बढ़ जाता है और वे होस्ट की गई सामग्री के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

प्रकाशक वर्गीकरण और जवाबदेही:

- मध्यस्थों के विपरीत, प्रकाशक अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री बनाने, संपादित करने और नियंत्रित करने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। वे जो जानकारी प्रसारित करते हैं, उसके लिए वे पूरी तरह से कानूनी रूप से जिम्मेदार होते हैं और अगर सामग्री अपमानजनक, भ्रामक या कानूनी मानकों का उल्लंघन करती है, तो उन्हें कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है:

- » **संपादकीय प्राधिकार:** प्रकाशक संपादकीय निरीक्षण करते हैं, जिससे उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होने वाली सामग्री पर नियंत्रण प्राप्त होता है।
- » **प्रत्यक्ष कानूनी उत्तरदायित्व:** प्रकाशक सभी सामग्री के लिए उत्तरदायी हैं, जिससे उल्लंघन के लिए उन पर आपराधिक दंड लगाया जा सकता है।

प्रमुख सरकारी चिंताएं:

- » **चुनिंदा समूह द्वारा संपादकीय नियंत्रण:** सरकार का कहना है कि विकिपीडिया के संपादन मॉडल में स्वयंसेवी संपादकों का छोटा समूह महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, जिससे सामग्री में विषयो को लेकर पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकता है।
- » **गलत सूचना और पूर्वाग्रह का खतरा:** गलत सूचना और अपमानजनक सामग्री के बारे में चिंता व्यक्त की गई है, जैसा कि एएनआई मामले में हुआ, जोकि विकिपीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है।

भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म विनियमन के निहितार्थ:

- » **विकिपीडिया के लिए उत्तरदायित्व की सुरक्षा समाप्त:** यदि विकिपीडिया को प्रकाशक के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है, तो वह अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होगा, जिससे मध्यस्थों को दी जाने वाली सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।
- » **सहयोगी प्लेटफॉर्मों के लिए संभावित परिणाम:** यदि विकिपीडिया को प्रकाशक माना जाता है, तो समान प्लेटफॉर्मों को सख्त नियामक मानकों का सामना करना पड़ सकता है, जोकि सहयोगी सामग्री निर्माण पर निर्भर होते हैं।
- » **सामग्री मॉडरेशन पर व्यापक प्रभाव:** यह मामला प्लेटफॉर्मों की सामग्री मॉडरेशन में भूमिका और जिम्मेदारी पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, जिससे मध्यस्थ और प्रकाशक वर्गीकरण में कानूनी सुधार की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)

वार्षिक सभा का सातवां सत्र

सन्दर्भ: हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की सातवीं वार्षिक सभा नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई। इस सभा में 103 सदस्य देशों और 17 हस्ताक्षरकर्ता देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 29 देशों के मंत्री भी सम्मेलन में सम्मिलित हुए, जिन्होंने सौर ऊर्जा को वैश्विक सतत विकास के मुख्य उत्प्रेरक के रूप में बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

सत्र के दौरान प्रमुख पहल:

Face to Face Centres



08 November 2024

इस सम्मेलन में विशेष रूप से अल्प विकसित देशों (LDCs) और लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए कई नई पहलें घोषित की गईं:

- **सौर डेटा पोर्टल:** यह एक वास्तविक समय मंच है, जो सौर संसाधनों, परियोजना निष्पादन और निवेश अवसरों पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। यह पोर्टल हितधारकों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने में सहायता करेगा।
- **वैश्विक सौर सुविधा:** इस पहल का उद्देश्य कम सेवा वाले क्षेत्रों में सौर परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक पूंजी को सुलभ बनाना है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक पायलट प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा है, जिसमें भारत, आईएसए, ब्लूमबर्ग और चिल्ड्रन्स इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन की ओर से महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धताएं हैं।
- **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना:** एलडीसी और एसआईडीएस में सौर परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए परियोजना लागत का 35% तक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, जिससे अधिक समावेशी सौर ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा।
- **नेतृत्व चुनाव:** 2024-2026 के कार्यकाल के लिए आईएसए के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष के चुनाव हुए, साथ ही एक नए महानिदेशक की घोषणा की गई, जो मार्च 2025 में पदभार ग्रहण करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में संयुक्त राष्ट्र

जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी21) में की गई थी।

आईएसए के उद्देश्य और लक्ष्य:

- आईएसए का मुख्य मिशन वैश्विक ऊर्जा संकट को दूर करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सौर ऊर्जा समाधान जुटाना है। संगठन अपनी महत्वाकांक्षी 'टुवर्ड्स 1000' रणनीति का पालन करता है, जो 2030 तक हासिल करने के लिए चार मुख्य लक्ष्य निर्धारित करता है:
- 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना, सौर ऊर्जा को किफायती और सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।
- स्वच्छ और टिकाऊ सौर ऊर्जा समाधान प्रदान करके, विशेष रूप से विकासशील देशों में, 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना।
- 1000 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करने से ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा की वैश्विक हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- सौर ऊर्जा को अपनाकर वैश्विक CO2 उत्सर्जन को प्रति वर्ष 1000 मिलियन टन तक कम करना, जिससे वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में योगदान मिलेगा।

मुख्यालय:

- आईएसए का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) में स्थित है।

पावर पैक न्यूज

उत्तराखंड में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ADB ने भारत के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने उत्तराखंड में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस पहल का उद्देश्य बाढ़ और भूस्खलन जैसे जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करते हुए जल आपूर्ति, स्वच्छता, गतिशीलता और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। इस परियोजना को यूरोपीय निवेश बैंक और राज्य सरकार द्वारा कुल 465 मिलियन डॉलर का सह-वित्तपोषित किया गया है।
- एशियाई विकास बैंक (ADB) 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। बैंक एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालय भी रखता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव

- रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, जिसमें उन्हें 295 इलेक्टोरल वोट और 73,236,927 लोकप्रिय वोट मिले। उनकी प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट और 68,859,041 लोकप्रिय वोट मिले।
- ट्रम्प एक सदी से भी अधिक समय में गैर-लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना

Face to Face Centres



08 November 2024

और जॉर्जिया जैसे प्रमुख स्विंग राज्यों में जीत हासिल की।

- ट्रम्प का एजेंडा सीमा सुरक्षा, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसका वैश्विक राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। ट्रम्प की जीत से वैश्विक राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, खासकर व्यापार, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे क्षेत्रों में।
- ट्रम्प द्वारा 20 जनवरी, 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली जाएगी। उनके साथी जेडी वेंस उपराष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे।
- संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों के रूप में कार्य करता है, और सशस्त्र बलों का कमांडर-इन-चीफ भी होता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद II के अनुसार, राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को क्रियान्वित करने और लागू करने का काम सौंपा गया है।



हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, 2024

- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक, साल 2024 में सबसे मजबूत सिंगापुर का पासपोर्ट है, जो 195 देशों में वीजा-मुक्त पहुँच प्रदान करता है। इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस दूसरे स्थान पर हैं।
- भारत 83वें स्थान पर है, जहाँ 58 देशों में वीजा-मुक्त पहुँच है। रैंकिंग उन देशों की संख्या पर आधारित है, जहाँ पासपोर्ट धारक बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन 191 देशों में पहुँच के साथ तीसरे स्थान पर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 8वें स्थान पर है, जहाँ 186 देशों में वीजा-मुक्त पहुँच है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान के हैं।
- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक वैश्विक रैंकिंग है जो देशों के साधारण पासपोर्ट द्वारा दी गई यात्रा स्वतंत्रता का मूल्यांकन करती है। यह पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंक करता है, जहाँ उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुँच सकते हैं। 2005 में हेनले एंड पार्टनर्स वीजा प्रतिबंध सूचकांक के रूप में लॉन्च किया गया, इसे जनवरी 2018 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया।



अनिल प्रधान को ग्रामीण विकास के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया

- हाल ही में ओडिशा के 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को ग्रामीण विकास में उनके विशिष्ट योगदान के लिए तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- यह पुरस्कार अर्थशास्त्री और प्रशासक डॉ. रोहिणी नैयर की स्मृति में रोहिणी नैयर फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था, जिनका 2021 में निधन हो गया था। पुरस्कार में 10 लाख का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी शामिल है।
- अनिल प्रधान (एक नवोन्मेषी इंजीनियर और शिक्षाविद्) ओडिशा के बराल क्षेत्र के निवासी हैं और उन्होंने भोपाल में उच्च शिक्षा प्राप्त की। एशिया की पहली विश्वविद्यालय रॉकेट टीम, वीएसएलवी के मुख्य डिजाइनर के रूप में प्रसिद्ध प्रधान ने ग्रामीण समुदायों के उत्थान के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार और जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने पर अपने प्रयास केंद्रित किए हैं।
- पुरस्कार समारोह के दौरान डॉ. नैयर के बहुआयामी गरीबी के आकलन में योगदान को रेखांकित किया गया और इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा ग्रामीण विकास की कुंजी है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को सक्रिय रूप से समर्थन देने के लिए नागरिक समाज से आह्वान किया, साथ ही प्रधान जैसे प्रतिबद्ध व्यक्तियों के प्रभाव को भी उजागर किया।
- इस वर्ष के पुरस्कार विजेता का चयन शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं के निर्णायक मंडल द्वारा किया गया, जिसमें प्रधान के ग्रामीण विकास और सामाजिक उत्थान में प्रभावशाली कार्य को मान्यता दी गई।



Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR: 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR: 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029



ध्येयias.com